



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 930]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2017/चैत्र 13, 1939

No. 930]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2017/CHAITRA 13, 1939

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ.1045 (अ). — सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन राज्य आयुष सोसायटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) को सहायता अनुदान उपलब्ध कराके केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच निधियों की हिस्सेदारी पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और हिमालयी राज्यों का निधियन पैटर्न 90:10 में है; और बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम का निधियन शत प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है; और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियन पैटर्न 60:40 के अनुपात में है;

और मंत्रालय द्वारा दिए गए सहायता अनुदान का प्रयोग राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन राज्य आयुष सोसायटी द्वारा आयुष अस्पतालों या आयुष औषधालयों या अपने-अपने राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पतालों के माध्यम से रोगियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को औषधियां उपलब्ध कराने या चिकित्सक से परामर्श (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) करने के लिए किया जाता है;

और इस स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से उपगत में पूर्णतः या आंशिक आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) कोई व्यक्ति जो इस स्कीम के अधीन नकद प्रसुविधा या सेवाएं प्राप्त करने का पात्र है उससे उसके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार ऐसे किसी व्यक्ति से और जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31-03-2018 तक आधार नामांकन कराने के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्यांक अभिप्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक संबंधित विभाग से , जो किसी व्यक्ति से आधार संख्यांक देने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है और यदि कोई आधार नामांकन केंद्र उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में उस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक संबंधित विभाग से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा होगी;

यह कि जब तक उस व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन लाभ निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जायेंगी, अर्थात् :-

(क) (i) यदि उस व्यक्ति ने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची;

या

(ii) नीचे पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) (i) मतदाता पहचान पत्र, या (ii) स्थाई खाता संख्यांक (पैन) कार्ड, या (iii) पासपोर्ट; या (iv) राशन कार्ड; (v) कर्मचारी सरकारी पहचान कार्ड ; या (vi) फोटो सहित बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक (vii) मनरेगा कार्ड या (viii) ईसीएचएस कार्ड, या ईएसआईसी कार्ड; या सीजीएचएस कार्ड, या (ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चलान अनुज्ञप्ति , या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्ष पत्र पर जारी ऐसे सदस्य का फोटो पहचान प्रमाण- पत्र; या (xi) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

परन्तु यह भी कि जब किसी फायदाग्राही को आपातकालीन उपाय के रूप में प्रसुविधाओं का उपभोग करने की आवश्यकता होती है तो उसे प्रसुविधाओं का उपभोग करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पैरा 1 के उप पैरा (3) में उल्लिखित उपर्युक्त अपेक्षाओं पश्चातवर्ती रूप से पालन करने के अधीन रहते हुए ऐसी प्रसुविधाएं लेने से इंकार नहीं किया जाएगा ।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन को भारसाधक सम्बंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा अर्थात्:-

(क) आयुष अस्पतालों या आयुष औषधालयों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पतालों के सहस्थापित आयुष इकाईयों के माध्यम से स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31-03-2018 तक अनेक क्षेत्रों पर उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों में नामांकन करने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि, फायदाग्राही नजदीकी ब्लॉक, या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधन संबंधित विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी तथा फायदाग्राहियों से उनके नाम, पता , मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरणों को देते हुए आयुष अस्पतालों या आयुष औषधालयों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पतालों में सहस्थापित आयुष इकाईयों या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सम्बद्ध कर्मचारियों या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अनुरोध रजिस्टर कराने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. जेड.28015/56/2016-एचएंडडी सेल (पार्ट-I)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1045(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of AYUSH (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the National AYUSH Mission (hereinafter referred to as the Scheme) as a Centrally Sponsored Scheme by providing Grant-in-Aid to the State AYUSH Society (hereinafter referred to as the Department) under the State Government or Union territory Administration;

And whereas, the sharing of funds between the Government of India and State Government is in the ratio of 60:40 for all States except the North Eastern Region (NER) States and three Himalayan States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand) and the funding pattern for NER and Himalayan States is 90:10; And whereas, for Union territories without legislature, the Scheme is funded cent percent by the Central Government; and for Union territories with legislature, the funding pattern is in the ratio of 60:40;

And whereas, the Grant-in-Aid given by the Ministry is used by the State AYUSH Society under the State Government or Union territory Administration for providing medicines or consultation with doctors (hereinafter referred to as the benefits) to the patients (hereinafter referred to as the beneficiaries) through the AYUSH Hospitals or AYUSH dispensaries or co-located AYUSH Units at the Primary Health Centres or Community Health Centres or District Hospitals in the respective State or Union territory;

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve full or partial recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the cash benefits or services under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) An Individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who do not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31-03-2018, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank / Post office Passbook with Photo (vii) MGNREGS card; or (viii) ECHS Card; or ESIC Card; or CGHS Card; or (ix) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose:

Provided also that when a beneficiary needs to avail benefits as an emergency measure, he or she shall not be denied such benefits subject to his or her subsequently complying to above requirement mentioned in sub-para (3) of para 1 within a period of 30 days from the date of availing the benefits.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (a) Wide publicity through media and individual notices shall be given via AYUSH Hospitals or AYUSH dispensaries or co-located AYUSH units at Primary Health Centres or Community Health Centres or District Hospitals in the State or Union territory to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31-03-2018, in case they are not

already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned department in charge of implementation of the scheme in State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the AYUSH Hospitals or AYUSH dispensaries or co-located AYUSH units at Primary Health Centres or Community Health Centres or District Hospitals or the concerned official of the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No.Z.28015/56/2016 – H&D cell (Part-I)]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.